जो शेयर घटे, विश्लेषक उनसे हटे

अग्रणी 500 शेयरों में से एक तिहाई शेयरों को विश्लेषकों ने अपने नजरिये से किया बाहर

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 26 नवंबर

कारोबारी अनिश्चितता, भारी-भरकम कर्ज और कंपनी प्रशासन के मसलों का सामना कर रही फर्मों के शेयरों का कवरेज विश्लेषक छोड़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, अग्रणी 500 कंपनियों में से एक तिहाई से ज्यादा ने उनके शेयरों को कवर करने वाले विश्लेषकों की संख्या में कमी देखी है। जिन फर्मों से सबसे ज्यादा विश्लेषक दूर हुए उनमें डिश टीवी, येस बैंक और जेएसडब्ल्यू एनर्जी शामिल है।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि विश्लेषक किसी शेयर का कवरेज तब छोड़ते हैं जब उन्हें कंपनी की किस्मत में नाटकीय बदलाव के कारण आय का अनुमान जाहिर करना मुश्किल हो जाता है।

एनबीएफसी, दूरसंचार और ज्यादा पूंजी वाले अन्य क्षेत्र की कंपनियों का उस सूची में वर्चस्व है जिनका कवरेज एक साल पहले की तुलना में कम विश्लेषक कर रहे हैं। नुकसान उठाने वाली कंपनियों की बढ़ती संख्या के साथ शेयरों का कवरेज छोड़ने वाले विश्लेषकों की संख्या बढ़ रही है।

वैसे शेयर जहां कवर करने वाले विश्लेषकों की घटी संख्या

कंपनी	शेयर कवर करने वाले विश्लेषकों की संख्या	
	एक साल पहले	अब
डिश टीवी इंडिया	25	14
येस बैंक	48	40
डीएचएफएल	12	4
सीजी पावर	11	3
वीए टेक वाबैग	20	12
जीएसके कंज्यूमर	24	16
जेएसडब्ल्यू एनर्जी	24	17
वोडाफोन आइडिया	28	21
इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस	15	8
पावर ग्रिड	34	28

स्रोत : ब्लूमबर्ग
संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

बीएसई-500 में शामिल कंपनियों में से 48 ने वित्त वर्ष 2018-19 में नुकसान दर्ज किया।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, प्रदर्शन के मोर्चे पर बार-बार निराशा से विश्लेषक ऐसे शेयरों का कवरेज छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। अगर मिडकैप या स्मॉलकैप का आकर्षण घट जाता है या ऐसे शेयरों में संस्थागत बिकवाली होती है तो विश्लेषक उसकी जगह अन्य सुर्खियां बनाने वाले शेयरों पर कवरेज शुरू करने के बारे में सोचेंगे। कंपनी या समूह पर असर डालने वाले कॉरपोरेट गवर्नेंस के मसले से भी कवरेज में कमी आती है। उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि विश्लेषकों से बातचीत करते रहने वाली ज्यादा पारदर्शिता और अच्छे कंपनी प्रशासन के मानकों वाली कंपनियों को ज्यादा विश्लेषक कवर करते हैं। इससे अक्सर ज्यादा संस्थागत निवेशकों की भागीदारी व बेहतर मूल्यांकन देखने को मिलता है।

विश्लेषक के कवरेज में गिरावट इसका संकेत भी है कि उस शेयर में खास तौर से संस्थागत निवेशकों की रुचि घट रही है।

स्वतंत्र विश्लेषक अंबरीश बालिगा ने कहा, अगर कोई विशिष्ट शेयर बेहतर नहीं कर रहा है और संस्थागत दिलचस्पी घट रही है तो उस शेयर के कवरेज का मतलब नहीं बनता। शोध को ब्रोकिंग आय का सहारा मिलना चाहिए। दिलचस्पी का अभाव आय में परिवर्तित नहीं होगा। कोई भी ऐसे शेयर का कवरेज महज प्रशंसा के लिए नहीं करना चाहता।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा, नए क्षेत्रों मसलन जीवन बीमा और संपत्ति प्रबंधन में कवरेज बढ़ाने के लिए विश्लेषक कुछ क्षेत्र में कवरेज बंद कर रहे हैं और उनकी जगह नए क्षेत्र को तवज्जो दे रहे हैं।

पिछली कुछ तिमाहियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में विश्लेषकों का कवरेज ज्यादा देखने को मिलता है। ज्यादातर विश्लेषक हालांकि कंपनी विशेष के घटनाक्रम को कवरेज में गिरावट की वजह बताते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि इसकी तकनीकी वजह भी हो सकती है। उद्योग के एक प्रतिभागी ने कहा, किसी खास ब्रोकरेज की तरफ से किसी क्षेत्र का कवरेज छोड़ना और विलय की घटनाएं भी उस शेयर में विश्लेषकों के कवरेज में गिरावट की वजह हो सकती है।

विगत में कुछ यूरोपीय निवेश बैंक अपना इक्विटी डेस्क बंद कर चुके हैं। साथ ही कुछ छोटे व मध्यम आकार वाले देसी ब्रोकरेज ने लागत घटाने के लिए अपना परिचालन कम किया है।

ओयो होटल्स का शुद्ध घाटा 2,385 करोड़ रुपये

एजेंसियां
नई दिल्ली, 26 नवंबर

होटल कंपनी ओयो होटल्स ऐंड होम्स को 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में 2,384.69 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। ओयो होटल्स द्वारा कंपनी पंजीयक के पास जमा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इससे पूर्व वित्त वर्ष में कंपनी को 360.43 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। कंपनी की परिचालन आय 2018-19 में बढ़कर 6,456.90 करोड़ रुपये रही, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 1,413.02 करोड़ रुपये रही थी। कंपनी के अनुसार वित्तीय परिणाम का अभी ऑडिट नहीं हुआ है और इसे मूल्यांकनकर्ताओं ने तैयार किया है न कि ऑडिटरों ने। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि ये आंकड़े मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित हैं। कंपनी ने कहा है कि मूल्यांकन के मानदंड मसलन शेयर कीमतें उचित बाजार कीमत पर आधारित होती हैं।

कंपनी के बयान में कहा गया है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये अंतिम अंकेक्षित वित्तीय आंकड़े नहीं हैं और अंकेक्षित आंकड़े कंपनी अपनी सालाना रिपोर्ट के साथ जारी करेगी और उसे कंपनी पंजीयक के पास भी जमा कराएगी। कंपनी ने कहा कि मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में कंपनी का परिचालन खर्च बढ़कर 6,131.65 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में 1,246.84 करोड़ रुपये रहा था। वर्ष के दौरान कर्मचारी को दिए जा रहे फायदे पर खर्च भी उछलकर 1,538.85 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। गुड़गांव की इस कंपनी का मूल्यांकन जून 2019 में 5.32 अरब डॉलर (36,658.34 करोड़ रुपये) आंका गया है।

{संक्षेप में

टीवीएस मोटर ने पहला बीएस-6 वाहन उतारा

टीवीएस मोटर ने टीवीएस अपाचे व आरटीआर 4वी सीरीज का पहला बीएस -6 वाहन उतार दिया है। नया बीएस-6 मॉडल मौजूदा के मुकाबले 9,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक महंगा होगा, जो उनके अलग-अलग संस्करण पर निर्भर होगा। कंपनी ने मंगलवार को टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी और टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी मोटरसाइकल उतार दिया। टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी की कीमत 1.24 लाख ररुपये और और टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी की कीमत 1.03 लाख रुपये है। देश भर में कंपनी की डीलरशिप पर मंगलवार से इसकी बुकिंग शुरू हो गई। *बीएस*

टोयोटा-सुजूकी शेयर सौदे को सीसीआई की मंजूरी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन और सुजूकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच अल्पांश हिस्सेदारी खरीद को मंजूरी दे दी। एक बयान के अनुसार सौदे के तहत सुजूकी मोटर में टोयोटा मोटर 4.94 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। वहीं टोयोटा मोटर में सुजूकी करीब 0.24 फीसदी हिस्सेदारी रखेगी। *भाषा*

एस्सेल की कंपनी में निवेश को बिड़ला एमएफ ने किया अलग

बीएस संवाददाता
मुंबई, 26 नवंबर

आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड ने एस्सेल समूह की कंपनी आदिलिंक इन्फ्रा ऐंड मल्टीट्रेडिंग में किए गए निवेश के लिए अलग पोर्टफोलियो बना दिया है, जिसे आम तौर पर साइडपॉकेटिंग कहा जाता है। बिड़ला म्युचुअल फंड की तीन योजनाओं एबीएसएल मीडियम टर्म फंड, एबीएसएल क्रेडिट रिस्क फंड और एबीएसएल डायनेमिक बॉन्ड फंड के जरिए आदिलिंक के ऋणपत्र में 793 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, जिसका भुगतान मार्च 2020 में होना है। निवेशकों को भुगतान में आदिलिंक की नाकामी के बाद साइड पॉकेट का सृजन हुआ है।

एबीएसएल एमएफ ने इन तीनों योजनाओं के निवेशकों के भेजे संदेश में कहा है, 25 नवंबर 2019 को अल्पांश निवेशकों को आदिलिंक की तरफ से भुगतान किया जाना था क्योंकि अल्पांश शेयरधारकों ने उन्हें मिले पुट ऑप्शन का इस्तेमाल किया था। हमें जानकारी मिली है कि कंपनी ने आज अल्पांश शेयरधारकों को पुनर्भुगतान नहीं किया। इसके बाद हमने आदिलिंक में हुए निवेश के लिए अलग पोर्टफोलियो बना दिया है।

तीनों योजनाओं के जरिए आदिलिंक के ऋणपत्रों में योजनाओं की कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों का 3.7 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी तक निवेश किया गया था। फंड हाउस ने कहा कि सड़क परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की मूल रूप से अनुमानित समयसीमा में विस्तार के कारण आदिलिंक पुनर्भुगतान नहीं कर पाई। साइड पॉकेट के तहत फंसी परिसंपत्तियों को मुख्य पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है।

तीन योजनाओं के जरिए आदिलिंक के ऋणपत्र में 793 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, जिसका भुगतान मार्च 2020 में होना है

अगर वहां से रिकवरी होती है तो इस कदम से मौजूदा निवेशकों के हितों को संरक्षित रखने में मदद मिलती है।

एबीएसएल एमएफ को उम्मीद है कि वह आदिलिंक से अपना बकाया वसूल करने में सक्षम होगी।

फंड हाउस ने निवेशकों को भेजे संदेश में कहा है, कुछ ही संभावित निवेशक हैं जो सड़क परिसंपत्तियों का सक्रियता से आकलन कर रहे हैं। हम सड़क परिसंपत्तियों की पूरी पोर्टफोलियो के लिए बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं और अभी यह प्रक्रिया अलग-अलग निवेशकों के साथ अलग-अलग चरणों में है। साख वाले थर्ड पार्ट वेंडर के जरिए किए गए अहम मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि जब पोर्टफोलियो के लिए मुद्रीकरण की प्रक्रिया कामयाबी के साथ पूरी हो जाएगी तो पूरा निवेश वापस लिया जा सकता है। हम जल्द से जल्द बकाया वसूलने के लिए सभी विकल्प तलाश रहे हैं।

आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी एमएफ को मिली रकम

एस्सेल समूह ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ और एचडीएफसी एमएफ को भुगतान कर दिया है। प्रवर्तक की तरफ से ज़ी एंटरटेनमेंट की हिस्सेदारी पिछले हफ्ते बेचने के बाद यह भुगतान हुआ है। अब एस्सेल समूह में आईसीआईसीआई प्रू एमएफ का निवेश शून्य रह गया, वहीं एचडीएफसी एमएफ को अभी भी कुछ बकाया वसूलना है।

सूत्रों ने कहा कि एस्सेल को शेयर के बदले कर्ज देने वाले म्युचुअल फंड मोटे तौर पर अपना बकाया वापस पाने में कामयाब रहे हैं, वहीं समूह के बुनियादी ढांचा उद्यम में निवेश अभी भी फंसा हुआ है।

आईसीआईसीआई प्रू एमएफ के प्रवक्ता ने कहा, हमें मूलधन के साथ उस पर ब्याज भी मिल गया है। अब आईसीआईसीआई एमएफ की किसी योजना का ज़ी की कंपनियों की तरफ से जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश नहीं है। उधर, एचडीएफसी एमएफ ने निवेशकों से कहा है कि उसे एनसीडी और उस पर बने ब्याज के लिए भुगतान का एक हिस्सा 166.8 करोड़ रुपये मिला है।

पीसी ज्वैलर की फिक्स्ड डिपॉजिट की रेटिंग घटी

अभिजित लेले
मुंबई, 26 नवंबर

केयर रेटिंग्स ने पीसी ज्वैलर लिमिटेड (पीसीजे) की सावधि जमाओं की रेटिंग बीबी से घटाकर बी कर दी है। नकदी की स्थिति और कंपनी के वित्तीय लचीलेपन में गिरावट के कारण रेटिंग घटाई गई है। पिछले कुछ महीने में फंड और गैर-फंड आधारित सीमाओं के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिला है। साथ ही बाजार पूंजीकरण में लगातार गिरावट आ रही है और कंपनी के नकद व बैंक शेष में भी कमी आ रही है।

इस रेटिंग में हालांकि कंपनी के अनुभवी प्रवर्तकों शक्तियों को समाहित करना जारी रखा गया है, जिनका रत्न व आभूषण उद्योग में परिचालन का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पीसीजे के नाम से यह स्थापित ब्रांड है। कंपनी की फंड व गैर-फंड आधारित सीमा का औसतन पूरा इस्तेमाल हुआ है। मई 2019 में समाप्त पिछले 12 महीने में इस्तेमाल का औसत 91.13 फीसदी रहा है। 30 सितंबर 2019 को कंपनी की इन्वेंट्री 5,310 करोड़ रुपये थी, जो 30 जून 2019 को 5,092 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2019 को 4,988.11 करोड़ रुपये थी। 30 सितंबर 2019 को इन्वेंट्री में इजाफे की वजह त्योहारी सीजन थी।

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

UNIVERSAL PRIME ALUMINIUM LIMITED

(the **"Company"**)
CIN: L28129MH1971PLC015207
Registered Office: 771, Century Bhavan, 1st Floor, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400025, Maharashtra,
Tel: +91 022-24304198 / 24307437,
E-mail: investors_uppl@yahoo.com; upalbby@gmail.com **Website**: www.universalprime.in
Contact Person: Ms. Priyanka Motwani, (Company Secretary/ Compliance Officer)

This Public Announcement (the "Public Announcement") is being issued by Mr. Prakash Kumar Mohta (the "Acquirer") to the Public Shareholders of Universal Prime Aluminium Limited (the "Company") in respect of the proposed acquisition of the entire Public Shareholding of the Company i.e. 41,43,665 (Forty one lakh forty three thousand six hundred sixty five) equity shares of face value Rs. 10/- each representing 52.01% of the total paid-up equity share capital of the Company and consequent voluntary delisting of the equity shares of the Company from the BSE Limited (the "BSE") pursuant to Regulation 10 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended, ("SEBI Delisting Regulations") and in accordance with the terms and conditions set out below ("Delisting Offer").

1. BACKGROUND OF THE DELISTING OFFER

1.1. History of the Company:
The Company was incorporated as "Sudarshan Engineering Private Limited" on July 05, 1971 under the Companies Act, 1956, Maharashtra at Bombay, which was changed to "Sudarshan Engineering Limited' on 1st May, 1974 and Company has further changed its name from "Sudarshan Engineering Limited" to "Universal Cans and Containers Limited" and Company has again changed its name to "Universal Prime Aluminium Limited" on 7th August, 1996. The registered office of the Company is situated at 771, Century Bhavan, 1st Floor, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 025, Maharashtra. The Company came out with an initial public offer in 1974. The Company was listed at BSE Ltd on October 15, 1974. The CIN of the Company is L28129MH1971PLC015207.

1.2. Capital Structure of the Company:
The Paid-up Capital of the Company as on the date of this Public Announcement is Rs.7,96,74,430/-.
Shareholding Pattern of Universal Prime Aluminium Limited as on 22nd November, 2019:

Particulars	No. of Equity Shares	% of Equity Share Capital
Promoters/Acquirers	38,23,778	47.99
Public	41,43,665	52.01
Total	**79,67,443**	**100.00**

1.3. The Acquirers are making this Offer to acquire 41,43,665 (Forty one lakh forty three thousand six hindered sixty five) equity shares (the "Offer Shares") representing 52.01% of the total paid-up equity share capital of the Company to the Public Shareholders (i.e. shareholders other than the Acquirer, Promoters and Promoter Group) in compliance with Chapter VII of the SEBI Delisting Regulations. If the Delisting Offer is successful in accordance with the Delisting Regulations, the Acquirer will apply to delist the equity shares from the BSE Ltd pursuant to and in accordance with the SEBI Delisting Regulations and on the terms set out in the Public Announcement, Letter of Offer and any other delisting offer documents. Consequent to such actions, the equity shares of the Company shall be delisted from the BSE Ltd.

1.4. The Acquirer vide his letter dated July 11, 2019 (the "**Acquirer Letter**") conveyed their intention to make a voluntary delisting offer to acquire the Offer Shares and delist the equity shares of the Company from BSE Ltd in accordance with the SEBI Delisting Regulations and requested the Board of Directors to approve the Delisting Offer and to seek the requisite approval from the shareholders through postal ballot and e-voting in accordance with the SEBI Delisting Regulations.

1.5. The Board of Directors, at its meeting held on July 27, 2019, took on record the Acquirer Letter and appointed M/s LSI Financial Services Pvt Ltd , as the Merchant Banker for carrying out due diligence as required in terms of Regulations 8(1A) (ii) and 8(1D) of the SEBI Delisting Regulations and notified the BSE on July 27, 2019.

1.6. The shareholders of the Company have given the approval for delisting of the securities of the Company pursuant to Postal Ballot Notice dated August 22, 2019 issued by the Company with a specific consent for dispensing with the Exit Price and discovery through book building method

1.7. The Company has been granted in-principle approval for delisting of the equity shares of the Company from BSE Ltd vide their letter no. LO\Delisting\VK\IP\295\2019-20 dated November 25, 2019 in accordance with Regulation 8(3) of the SEBI Delisting Regulations.

2. NECESSITY /JUSTIFICATION AND OBJECTIVES OF THE DELISTING OFFER

2.1. The objective of the Acquirer in making the Delisting Offer is inter-alia to:
(a) The objective of making the delisting offer is to obtain full ownership of equity shares of the Company, which will provide the promoter group with Operational flexibility to support the Company's business and future financing needs.
(b) Ongoing expenses with, maintenance of listing BSE Ltd will be reduced, including investor relations expenses;
(c) The management time can be dedicated to the Company's business, as time dedicated to compliance with listing requirements gets reduced.
(d) The Company incurs significant cost every year towards listing fee & other statutory compliances; which will reduce considerably;
(e) The Company does not have any business activities as on date & present revenue comprises interest/dividend income;
(f) The majority of shareholders are holding shares in physical form, hence there is less liquidity in the securities of the Company;
(g) There are no new business proposals under consideration & hence operations are likely to stagnate.
(h) Provide an exit opportunity to the public shareholders of the Company.

3. DETERMINATION OF THE EXIT PRICE

3.1. The Acquirer propose to acquire the equity shares of the Company from the Public Shareholders pursuant to a method prescribed in the SEBI Delisting Regulations.
The Acquirers have appointed LSI Financial Services Pvt Ltd, Merchant Banker for the purpose of determining the exit/ Floor price of the equity shares of the Company. As per the valuation report dated August 21, 2019 ("Valuation Report") the fair value per equity share of face value of Rs.10/- each of **Universal Prime Aluminium Limited** works out to **Rs 3.50/-.** Based on the Valuation Report the Acquirers in are making an offer to acquire the equity shares from the public shareholders at an exit price of **Rs.3.50 /- (Rupees Three and paisa fifty only)** per equity share.

4. ACTIVITY SCHEDULE FOR EXIT OFFER
Date of Opening of Offer (Inviting the positive consent) December 02, 2019
Date of Closing of Offer (Closing date of inviting positive consent) March 19, 2020

5. PROCEDURE FOR TENDERING

5.1. The Letter of Offer (along with necessary forms and instructions) inviting the Public Shareholders to tender their equity shares to the Acquirer will be dispatched to the Public Shareholders by the Acquirer whose names appear on the register of members of the Company and to the owner of the Equity Shares whose names appear as beneficiaries on the records of the respective depositories at the close of business hours on November 27, 2019.

5.2. The Delisting Offer is open to all Public Shareholders of the Company.

5.3. The shares can be tendered in demat form only in the demat account stated in the letter of offer. The public shareholders holding shares in the physical form shall get their shares demat before tendering of the shares as no physical shares shall be accepted in tender. As per the proviso to Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (notified by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018), effective from December 5, 2018, transfers of securities were not to be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Further, as per the press release dated December 3, 2018 read with press release dated March 27, 2019 issued by SEBI, with effect from April 1, 2019, the request for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository. Accordingly, the Company shall not accept the Equity Shares tendered under the Delisting Offer unless such Equity Shares are in dematerialized form.

6. METHOD OF SETTLEMENT

Upon finalization of the Basis of Acceptance as per the SEBI Delisting Regulations:
a) Upon fulfillment of the terms and conditions mentioned herein and receipt of the requisite regulatory approvals (if any), the consideration for shares will be paid by the Acquirer by way of cheque or demand draft or electronic transfer/NEFT/RTGS. The cheque or demand drafts will be dispatched to the Shareholders, at their own risk, by way of speed post / registered post. The Acquirer intends to dispatch the payment to Shareholders who have validly tendered their Offer Shares in this Exit Offer-following the receipt of duly filled in Form of Acceptance.
b) The Public Shareholders who have tendered their Shares which are found to be in order the consideration for such Shares will be settled on completion of the Exit period and the payment will be dispatched within Fifteen (15) working days from the end of the Exit Period.
c) In case of joint holders, the cheque / pay order / demand draft will be drawn in the name of the first named holders.

For and Behalf of the Acquirer
Sd/-
Mr. Prakash Kumar Mohta

Date: 27/11/2019
Place: Kolkata

थापर को सूचना उपलब्ध कराए सीजी पावर : सेबी

एजेंसियां
नई दिल्ली, 26 नवंबर

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने धोखाधड़ी से प्रभावित सीजी पावर ऐंड इंडस्ट्रियल सॉल्युशंस से बर्खास्त चेयरमैन गौतम थापर और अन्य को धोखाधड़ी की जांच के तहत की गई ऑडिट से जुड़ी वह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है, जिसकी उन्होंने मांग की है। थापर और अन्य ने अपने कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी मांगी हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 25 नवंबर को कंपनी से 4 दिसंबर तक उन्हें सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा है। नियामक ने सितंबर में थापर, सीजी पावर के मुख्य वित्त अधिकारी और दो अन्य निदेशकों के संदिग्ध सौदों में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर उन्हें पूंजी बाजार में लेनदेन से प्रतिबंधित कर दिया है।

सेबी ने आदेश में कहा, यह निर्देश दिया जाता है कि जो सूचना कंपनी के पास उपलब्ध है और जिसके बारे में थापर और अन्य निदेशकों द्वारा अनुरोध किया गया है, उसे 4 दिसंबर या उससे पहले उपलब्ध कराया जाए। नियामक ने कंपनी से ई-मेल का ब्योरा भी देने को कहास जिसका जिक्र ऑडिटर रिपोर्ट में किया गया है। उसी ई-मेल के जरिए सीजी पावर में कथित वित्तीय अनियिमितताएं सामने आईं।

सेबी ने अपने आदेश में सीजी पावर की कंपनी सचिव शिखा कपाड़िया से कहा है कि 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। सीजी पावर ने अगस्त में कहा था कि उसके निदेशक मंडल द्वारा शुरू की गई जांच में संचालन और वित्तीय मामलों में बड़ी चूक पाई गई है। इसमें कंपनी की कुछ संपत्तियों को गिरवी रखकर प्राप्त कर्ज की राशि को कंपनी के कुछ मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के खाते में डालना शामिल है।

साथ ही यह भी पता चला कि पहले की कुछ देनदारियों और दिए गए उधार को कम करके दिखाया गया था। कुल कथित धोखाधड़ी 3,000 करोड़ रुपये की बताई गई है। चेयरमैन पद से बर्खास्त थापर ने ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज की मांग की थी।

इससे पहले, सेबी ने बीएसई को कंपनी के 2015-16 और उसके बाद के खातों का विस्तृत फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने का निर्देश दिया था।

होंडा के मानेसर कारखाने में उत्पादन बहाल

होंडा मोटरसाइकिल ऐंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने मंगलवार को कहा कि उसके मानेसर संयंत्र में स्थायी श्रमिकों के साथ उत्पादन का काम फिर शुरू हो गया है। हालांकि नौकरी से निकाले गए ठेका श्रमिक अब भी संयंत्र के बाहर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। दोपहिया वाहन बनाने वाली जापान की कंपनी होंडा ने अपने इस संयंत्र में नवंबर के पहले हफ्ते में कामकाज बंद कर दिया था। 200 ठेका मजदूरों को काम से निकाले जाने को लेकर श्रमिकों ने हड़ताल कर दी थी। इस कारखाने में 1,900 स्थायी और 2,500 ठेका श्रमिक हैं।

कंपनी में 5 नवंबर से हड़ताल की स्थिति चल रही थी। उस दिन कथित रूप से कंपनी के प्रबंधकों ने कुछ ठेका मजदूरों को प्रवेश नहीं करने दिया था। कंपनी ने एक बयान में कहा, कंपनी ने 22 नवंबर को मानेसर संयंत्र में उत्पादन फिर शुरू करने का निर्णय किया।

सभी स्थायी श्रमिकों को 25-28 नवंबर के बीच में चार चरणों में ड्यूटी पर आने के लिए कह दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ श्रमिक संगठन ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया कि संयंत्र पर काम फिर शुरू करके वह गलत कर रही है। *भाषा*

ओला लंदन में ड्राइवरों को साथ जोड़ने लगी

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 26 नवंबर

दुनिया की अग्रणी टैक्सी सेवा-प्रदाता उबर का लंदन में परिचालन लाइसेंस निरस्त हो जाने के बाद भारतीय कैब फर्म ओला ने ब्रिटेन की राजधानी में लाइसेंस रखने वाले ड्राइवरों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। इसे अगले कुछ हफ्तों में लंदन में ओला की कैब सेवा शुरू होने का संकेत माना जा रहा है।

ओला ने मंगलवार को बयान में कहा कि लंदन में आवागमन सेवा मुहैया कराने के लिए लाइसेंसधारक ड्राइवर उसके ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस अभियान के जरिये लंदन के करीब 50,000 ड्राइवरों को ओला से जोड़ने की तैयारी है।

ओला ने ब्रिटेन में अपना परिचालन अगस्त 2018 में कार्डिफ शहर से शुरू किया था। उसके बाद सॉफ्टबैंक-समर्थित ओला ने ब्रिटेन के कई अन्य शहरों- बर्मिंघम, लिवरपुल, रीडिंग, ब्रिस्टल, बाथ, कॉवेंट्री और वारविक में भी अपनी सेवाओं का विस्तार कर दिया है। अब वह ब्रिटिश राजधानी में अपने कदम रखने की तैयारी में जुट गई है। ओला के अंतरराष्ट्रीय कारोबार प्रमुख साइमन स्मिथ ने कहा, 'आज हम लंदन के हजारों ड्राइवरों को ओला प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम आने वाले कुछ हफ्तों में इस शहर में अपना परिचालन शुरू करने वाले हैं। हमने लंदन के लिए एक सशक्त परिवहन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो लंदन परिवहन विभाग के ऊंचे मानदंडों के अनुकूल हैं।'

प्रतिद्वंद्वी फर्म उबर का लंदन में परिचालन लाइसेंस निरस्त होने के बाद ओला हुई सक्रिय

ओला को इस साल की शुरुआत में लंदन में परिचालन शुरू करने का लाइसेंस मिला था। इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ब्रिटेन के 27 इलाकों में पहले से ही 70 लाख यात्री कर रहे हैं। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी सख्त सुरक्षा मानदंडों पर खुद का खरा साबित किया है। ओला भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 250 से भी अधिक शहरों में कैब सेवाएं दे रही है। उबर का लंदन में परिचालन लाइसेंस कुछ दिन पहले ही निरस्त हुआ है। लंदन के परिवहन विभाग ने सुरक्षा मानकों पर बार-बार नाकाम रहने के बाद उसके लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया है।